

भीलवाड़ा में रेड डालने पहुंची टीम को देख भागा अकाउंटेंट:इनकम टैक्स विभाग घर में सर्च कर रहा

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

देशभर में करीब 150 ठिकानों पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश पर आयकर विभाग छपे की कार्रवाई जारी है। विभाग ने खामियां मिलने पर जांच का दायरा बढ़ाया था। इसके साथ ही 2 पॉलिटिकल पार्टी के ठिकानों पर रेड की गई।

इसमें राजस्थान आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा की ओर से दोनों पॉलिटिकल पार्टी के महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान में मौजूद 10 ठिकानों पर छपेमारी की गई। राजस्थान में भीलवाड़ा में यह कार्रवाई की गई है।

बीती रात हुई कार्रवाई में आयकर विभाग की टीम ने भीलवाड़ा में संजय कॉलोनी में रहने वाले एक अकाउंटेंट राजकुमार के घर रेड डाली। लेकिन, रेड की भनक लगते ही वह मौके से भाग निकला। हालांकि टीम अकाउंटेंट के घर पर सर्च कर रही है, जो अभी जारी है। विभाग के अधिकारी अभी किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से बच रहे हैं।

अब समझ लीजिए क्या है पूरा मामला

आयकर टीमों को पिछले 3 साल में दो पॉलिटिकल पार्टियों के



कमिशन काटकर 500 करोड़ रुपए का बोगस चंदा वापस लौटाने के सबूत मिले। इसके चलते आयकर विभाग ने कठौतियों और छूटों के फेक दावों को लेकर देशभर में करीब 150 ठिकानों पर सोमवार 14 जुलाई को छपेमारी की कार्रवाई की शुरुआत की।

जांच में आईटीआर तैयार करने वाले और बिचौलियों की ओर से संचालित संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तलाशी और जब्ती कार्रवाई में विभिन्न गुप्तों और संस्थाओं की

ओर से धोखाधड़ी करने के सबूत मिले। जानकारी के अनुसार, इसी कड़ी में बीती रात पुलिस ने सुभाष नगर थाना क्षेत्र की संजय कॉलोनी में एक और कार्रवाई को अंजाम दिया। खेड़खूट माताजी गली में रहने वाले राजकुमार के घर टीम ने रेड डाली। राजकुमार को टीम के आने की भनक लग गई और वो मौके से भाग निकला। टीम ने इसका कुछ दूरी तक सर्च भी किया लेकिन वो टीम को चकमा दे गया। ये युवक अकाउंटेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। रात से टीम इसके मकान पर जांच में जुटी है फिलहाल टीम

की कार्रवाई जारी है। सोमवार को भीलवाड़ा सहित प्रदेश भर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने 200 से ज्यादा स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। भीलवाड़ा में तिलक नगर में रहने वाले और अकाउंट का काम करने वाले एक व्यक्ति राजेश कोईवाल (सीए) के यहां सबसे पहले टीम पहुंची थी। इसके बाद पुर रोड स्थित गोविंदम प्लाजा में एक सीए के ऑफिस पर मंगलवार को कार्रवाई की। इन दोनों स्थानों से टीम ने कई डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए हैं, इसके साथ ही कुछ डेटा भी टीम को हाथ लगा है।

भीलवाड़ा में रेलवे ट्रैक पर मिली चचेरे भाई-बहन की लाश:डॉक्युमेंट्स से हुई पहचान



द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ मार्ग अंडर ब्रिज के पास रेलवे ट्रैक के पास युवक-युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी टीम और पुलिस भी मौके पर पहुंची।पुलिस ने दोनों शव जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखवा परिजनों को सूचित किया। परिजनों ने इनकी पहचान कजिन भाई बहन के रूप में की। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इन दोनों की मौत ट्रेन से गिरने से हुई या उन्होंने ट्रेन से कूदकर सुसाइड किया।

ट्रैक के पास मिली थी दोनों की लाश

जीआरपी के चौकी प्रभारी खलील अहमद ने बताया कि मंगलवार को स्टेशन मास्टर से सूचना मिली थी कि भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन अंडर ब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक और युवती की बाँड़ी पड़ी है। इस पर मौके पर पहुंचे या रेलवे ट्रैक के पास एक युवक युवती की बाँड़ी पड़ी थी जिस पर पर चोट के निशान थे। दोनों की बाँड़ी को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी

हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी भिजवाया इनके पास मिले डॉक्युमेंट के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई। इसके बाद सीकर जिले के दातारामगढ़ से किशनलाल रेगर सहित कुछ लोग भीलवाड़ा पहुंचे किशन लाल ने मृतक की पहचान अपने भतीजे ओमप्रकाश (32) पिता पोखर राम रेगर निवासी दातारामगढ़ और युवती की पहचान किशनगढ़ रेनवाल निवासी पूजा (25) पत्नी कमलेश रेगर के रूप में की।

सुसाइड या हादसा, जांच में जुटी पुलिस

अंकल ने बताया कि ये दोनों चचेरे भाई बहन थे। उनका भतीजा पिछले 5 साल से बेंगलुरु कर्नाटक में मार्बल का काम कर रहा था और वो पूजा को लेकर सीकर लौट रहा था, इसी बीच पुलिस से सूचना मिली कि दो बाँड़ी मिली है। उस पर हम यहां पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों की बाँड़ी का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया। इन दोनों ने ट्रेन से कूदकर सुसाइड किया है या ट्रेन से गिरने से उनकी मौत हुई है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है।

दो पॉलिटिकल पार्टी के ठिकानों पर आयकर रेड:500 करोड़ का लिया बोगस चंदा

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

देशभर में करीब 150 ठिकानों पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश पर आयकर छपे की कार्रवाई की गई। आयकर विभाग के जांच का दायरा बढ़ने पर 2 पॉलिटिकल पार्टी के ठिकानों पर रेड की गई। राजस्थान आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा की ओर से दोनों पॉलिटिकल पार्टी के महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान में मौजूद 10 ठिकानों पर छपेमारी की गई। राजस्थान में भीलवाड़ा में यह कार्रवाई की गई है।आयकर टीमों को पिछले 3 साल में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के कमिशन काटकर 500 करोड़ रुपए का बोगस चंदा वापस लौटाने के सबूत मिले है। आयकर विभाग छपेमारी में मिले डॉक्यूमेंट और डिजिटल डिवाइस की पड़ताल कर रही है। दरअसल, आयकर विभाग ने कठौतियों और छूटों के फेक दावों को लेकर देशभर में करीब 150 ठिकानों पर सोमवार 14 जुलाई को छपेमारी की कार्रवाई की शुरुआत की। जांच में आईटीआर तैयार करने वाले और बिचौलियों की ओर से संचालित संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में तलाशी और जब्ती कार्रवाई में विभिन्न गुप्तों और



संस्थाओं की ओर से धोखाधड़ी करने के सबूत मिले।

बढ़ाया जांच का दायरा, 2 पॉलिटिकल पार्टी मिली

राजस्थान आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने जांच का दायरा बढ़ाया गया। इनकम टैक्स जालसाजी संगठित गिरोह के संपर्क में मध्यप्रदेश की भारतीय सामाजिक पार्टी और महाराष्ट्र की युवा भारत आत्मनिर्भर दल का होना सामने आया। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छपेमारी शुरू की। आयकर टीमों ने दोनों पॉलिटिकल पार्टी के महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान में 10 ठिकानों पर रेड की। भारतीय सामाजिक पार्टी का रजिस्टर्ड

ऑफिस मध्यप्रदेश के अलीराजपुर और युवा भारत आत्मनिर्भर दल का महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं। भारतीय सामाजिक पार्टी के बैंक अकाउंट राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में मौजूद है।

पिछले 3 साल का मिला ब्योरा आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी चंदे में आए रुपयों को राजनीतिक गतिविधियों में यूज नहीं लेती थी। दोनों ही पार्टियों की ओर से कमिशन पर बोगस चंदा लिया जाता था। आयकर टीमों की कार्रवाई में पिछले 3 साल में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के 500 करोड़ रुपए का बोगस चंदा लेने का पता चला है। दोनों ही पार्टियों को काफी चंदा राजस्थान के अनेक लोगों से

मिला है। डोनेशन के जरिए मिलने वाले रुपयों में पार्टी की ओर से अपना कमिशन रोककर बोगस चंदा कैश लौटा देते थे।

बोगस डोनेशन वालों पर गिरेगी गाज

आयकर विभाग की ओर से चंदे के अलावा फर्जी चिकित्सा खर्च, बच्चों की फर्जी ट्यूशन फीस, मकान किराया आदि की रसीदों को लेकर ली जा रही छूट के फर्जीवाड़े में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इस तंत्र में काफी सीए, कर सलाहकार सहित विभिन्न व्यक्तियों के शामिल होने पर उन्हें कवर किया गया है। आयकर विभाग की अगली कार्रवाई बोगस डोनेशन देने वाले आयकर करदाताओं पर हो सकती है।

लगजरी बस से पकड़ी 4 लाख की अवैध शराब: तीन बड़ी ट्रॉलियों में लगेज के साथ रखी थी

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, इसी के तहत पुलिस ने एक लगजरी बस से 4 लाख से अधिक रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने लगजरी बस सहित ड्राइवर कंडक्टर और एक उनके एक साथी को गिरफ्तार किया है। बस की डिक्वी में लगेज के साथ छुपाई थी

मामला कारोई थाना क्षेत्र का है,थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि तहसील कार्यालय के सामने नाकाबंदी की जा रही थी,इस दौरान भीलवाड़ा की ओर से एक ट्रैवल्स बस आई जिसे रोककर बस की तलाशी शुरू की तो बस की पीछे की डिग्गी में सब्जियों व अन्य सामान के साथ 3 बड़े ट्रॉली बैग थे, इन्हें चेक किया तो इनके अंदर कार्टून में अलग-अलग ब्रांड की शराब की बाँटल पाई गई। जिनकी कीमत 4 लाख 32 हजार रुपए है। ड्राइवर-कंडक्टर सहित तीन गिरफ्तार पुलिस ने इस मामले में बस



ड्राइवर, कंडक्टर और उनके एक साथी को आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस बस और अलग-अलग ब्रांड की कुल 108 बाटल शराब को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल बस ड्राइवर सुंदर (37) पिता जगदीश धानका निवासी भिवानी हरियाणा, कंडक्टर अविनाश पिता भूपराम कस्वा निवासी श्रीगंगानगर, विनोद (22) पिता नानुराम रेवाड़ी निवासी चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया है।

कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में कारोई थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, एसएसआई दयाल राजोरा, हेड कॉन्स्टेबल मुकेश,कॉन्स्टेबल अनिल अशोक ,राजपाल ,खेमराज ,राधेश्याम ,दिनेश ,रामचंद्र और विजेंद्र शामिल रहे है।

सम्पादकीय

भारतीयों को सशक्त कर रहा है चीन

डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका की दोबारा कमान संभालने के बाद से वैश्विक ढांचे में अस्थिरता-अनिश्चितता का भाव निरंतर बढ़ने पर है। नीति निर्माण से जुड़े उनके मनमाने एवं एकतरफा रवैये का असर अमेरिका के दोस्तों के साथ ही उसके प्रतिद्वंद्वियों पर भी समान रूप से पड़ रहा है। यूक्रेन-रूस युद्ध, पश्चिम एशिया में जारी टकराव, दक्षिण एशिया में आतंक का बढ़ता प्रकोप और चीन की आक्रामकता में हो रही वृद्धि जैसे पहलू भी अंतरराष्ट्रीय मामलों की दशा-दिशा पर अपना असर डाल रहे हैं। समय के साथ वैश्विक मामलों में



भारत की भूमिका भी बढ़ी है, तो वैश्विक ढांचे को नया आकार देने में भारतीयों की आकांक्षाएं भी उसी अनुपात में बढ़ रही हैं। आब्जर्वरिसर्च फाउंडेशन-ओरआएफ ने एक सर्वे के जरिये इन आकांक्षाओं की थाह लेने का प्रयास किया है। इसमें कुछ दिलचस्प संकेत उभरते हैं। इस बार ओरआएफ का विदेश नीति संबंधी सर्वे चीन की चुनौतियों के संदर्भ में युवा भारत के मन की थाह लेने पर केंद्रित है। आखिर देश का युवा विदेश नीति संबंधी निर्णयों एवं चुनौतियों को किस रूप में देखता है। इस सर्वे में देश के 19 शहरों में 11 भाषाओं के जरिये 18 से 35 वर्ष की आयु के पांच हजार से अधिक युवाओं से संवाद किया गया। चूंकि यह सर्वे पिछले वर्ष 22 जुलाई से 26 सितंबर के बीच हुआ, इसलिए इसमें ट्रंप के दोबारा अमेरिका की कमान संभालने के प्रभाव से लेकर पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में आपरेशन सिंदूर जैसे अभियान एवं भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव पर नजरिया सामने नहीं आ सका, लेकिन इसकी व्यापक झलक जरूर मिलती है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और उनके प्रति भारत के दृष्टिकोण को लेकर हमारा युवा वर्ग क्या सोचता-समझता है। सबसे प्रमुख पहलू तो यह उभरा कि भारत की विदेश नीति के प्रति समर्थन में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और करीब 88 प्रतिशत उत्तरदाताओं का रवैया इसे लेकर सकारात्मक है। वर्तमान परिस्थितियों से निपटने में भारत की सफलता को लेकर यह बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। चीन को लेकर भावनाओं का आकलन करना था तो उत्तरदाताओं के बीच भी इस मुद्दे की महत्ता बखूबी महसूस हुई। 89 प्रतिशत ने माना कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद 86 प्रतिशत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दूसरी, जबकि 85 प्रतिशत ने पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को तीसरी सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में चिह्नित किया। भले ही भारत-चीन ने तनाव घटाने की दिशा में कुछ प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि रिश्तों में सुधार को लेकर उम्मीद बहुत कम है। एक साल पहले चीन को लेकर भरोसे की जो कमी थी, वह और ज्यादा बढ़ गई। गलवन के हिंसक संघर्ष के पांच साल बाद भी चीन के प्रति दुराव कम नहीं हुआ है। अधिकांश युवा उसके उभार को लेकर चिंतित होने के साथ ही उसे एक सैन्य खतरे के रूप में भी देखते हैं। इनमें 81 प्रतिशत तिब्बत पर अवैध कब्जे को रिश्तों में बढ़ा अवरोध मानते हैं। करीब 84 प्रतिशत युवा आर्थिक साझेदारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जो चीन से आयात घटाने के हिमायती हैं। वहीं, 79 प्रतिशत युवाओं का मानना है कि चीन की बीआरआई परियोजना से दूर रहने का फैसला हमारे लिए हितकारी है। भारत के लोगों और खासकर युवाओं के बीच रणनीतिक परिदृश्य पर हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। इसके बाद दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बारी आती है। इसमें सामुद्रिक मोर्चे पर चीन के बढ़ते दखल की चिंता झलकती है। भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति को भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। सर्वाधिक 72 प्रतिशत युवा नेपाल को सबसे भरोसेमंद पड़ोसी के रूप में देखते हैं। इसके बाद भूटान एवं श्रीलंका का स्थान आता है। बांग्लादेश को लेकर भरोसा 2022 से लगातार घटने पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रति सर्वाधिक संशय बना हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर नजरिया पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सुधरा है,

प्रधान संपादक - दयाराम दिव्य

हरियालो राजस्थान अभियान के अन्तर्गत गृह रक्षा विभाग द्वारा जिले में किया गया वृक्षारोपण

भीलवाड़ा । अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर एवं निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा हरियालो राजस्थान अभियान के अन्तर्गत आगामी मानसून के दौरान वृक्षारोपण किये जाने के लिए गृह रक्षा विभाग को 30 सितम्बर तक 500 वृक्षों का वृक्षारोपण करने के निर्देश प्रदान किए गए जिसके तहत गृह रक्षा विभाग के कमाण्डेन्ट ललित बिहारी व्यास के निर्देशन में हरियालो राजस्थान के कार्यक्रम को साकार करने के लिए कार्यालय, समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पर 150 पौधे एवं उपकेन्द्र (जहाजपुर पर



50 वृक्ष, गुलाबपुरा 40, गंगापुर 40) कुल 280 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार के छायादार व फल फूल वाले पौधे लगाए गए। इस अवसर पर होमगार्ड

प्रशिक्षणार्थियों, सदस्यों को ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण सुरक्षा हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने एवं उनका संरक्षण करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम का आयोजन कमाण्डेन्ट ललित

बिहारी व्यास के निर्देशन में गृह रक्षा विभाग के कम्पनी कमाण्डर कर्मजीत सिंह के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में गृह रक्षा विभाग के लेखाधिकारी द्वितीय गजानन्द कुमावत, मुख्य आरक्षी शान्तिलाल, वरिष्ठ सहायक नरेन्द्र सिंह मीणा, वरिष्ठ सहायक देवेन्द्र सिंह, आरक्षी मंजित, महावीर प्रसाद एवं स्वयंसेवक राजनारायण श्रोत्रिय, राकेश कुमार, रमेशचन्द्र, हरलेश कुमार, विशाल, सदाकत अली, छोटूलाल आदि मौजूद रहे।

विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष में एक दिवसीय डिजिटल स्किल्स शिविर का आयोजन

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

फुलियाकलां । विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टीम भगत सिंह आर्मी के सहयोग से एक दिवसीय डिजिटल स्किल्स शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं को डिजिटल युग में आवश्यक कौशलों से परिचित कराने और उनके आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करने हेतु आयोजित किया गया। इस शिविर में प्रतिभागियों को कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, इंटरनेट उपयोग, ऑनलाइन शिक्षा के



साधन, डिजिटल सुरक्षा, और चेट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही, प्रतिभागियों को मोबाइल और कंप्यूटर का सही

उपयोग सिखाया गया। जिससे वे भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बालक-बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग

लिया। प्रशिक्षकों द्वारा विषय को सरल भाषा में समझाते हुए युवाओं के सवालों का समाधान भी किया गया। शिविर में टीम भगत सिंह आर्मी के सदस्यों की सक्रिय भूमिका रही।

इस अवसर पर युवाओं ने डिजिटल तकनीकों को सीखने की दिशा में अपनी रूचि और उत्साह प्रदर्शित किया। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में ऐसे और भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी तकनीकी दुनिया से कदम से कदम मिला सकें।

राजीविका के 45 क्लस्टरों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा । राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के अंतर्गत मंगलवार को जिले की सभी ब्लॉक से जुड़ी 45 क्लस्टर के क्लस्टर मैनेजर और सीएलएफ अकाउंटेंट और सीएलएफ अध्यक्ष की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

राजीविका के अमित जोशी ने बताया कि कार्यशाला में सभी क्लस्टर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी की प्रेजेंटिंग की जाती है जिसमें उनके कार्यों की क्षमता का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है और सरकारी योजनाओं के साथ साथ क्लस्टर पर सभी कैडर द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली गई। जो महिलाये आत्मनिर्भर बनी है उनके द्वारा आत्मकथा के रूप में पहले उनकी क्या स्थिति थी समूह में जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए है और उन्होंने कितनी



महिलाओं की जिंदगी में बदलाव किए है के बारे में चर्चा की गई। क्लस्टर मैनेजर जयश्री टाक ने बताया कि राजीविका में जुड़ने से मुझे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर मिला है और समूह से जुड़कर आर्थिक मदद प्राप्त कर मजबूत हुई है। लेखापाल पूजा स्वामी ने बताया कि क्लस्टर से जुड़ी 5 हजार महिलाओं के लेखाजोखा का काम कर उनको आर्थिक रूप से मजबूत बना रही

हुं। लेखापाल संध्या बैरवा ने बताया कि मैं स्वयं महिला निधि बैंक से ऋण लेकर स्वरोजगार कर रही हूँ और क्लस्टर से जुड़ी 3 हजार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सभी को महिला निधि बैंक से ऋण दिलवाकर उनकी आजीविका में बढ़ोतरी का कार्य किया गया है। क्लस्टर मैनेजर मरुधर कंवर ने कहा कि बैंकों से और परियोजना से ऋण लेकर आर्थिक रूप से मजबूत

हुई हूँ और स्वयं आजीविका में बढ़ोतरी कर सभी क्लस्टर से जुड़ी 4 हजार महिलाओं के जीवन में बदलाव हो रहा है। सभी क्लस्टर स्टाफ ने नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण पर विचार व्यक्त किये। कार्यशाला में जिला प्रबंधक रामप्रसाद शर्मा, ब्लॉक परियोजना प्रबन्धक चंद्रशेखर शर्मा, आरपीएआरपी भगवती, लक्ष्मण उपस्थित रहे। सभी कैडर ने जल स्वच्छता की शपथ ली।

श्री गौ सेवा मित्र मंडल को हरि शेवा ट्रस्ट ने किया 51 हजार रुपए का सहयोग

द मूवमेंट ऑफ इंडिया

भीलवाड़ा । श्री गौ सेवा मित्र मंडल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा घायल और असहाय गोवंश के रेस्क्यू और उपचार के लिए चलाए जा रहे सेवा कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरि शेवा धर्मशाला ट्रस्ट के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने इक्यावन हजार रुपये का चेक भेंट कर आर्थिक

सहयोग प्रदान किया। यह आयोजन हरि शेवा धर्मशाला परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें आश्रम के संतों के साथ-साथ शहर के कई सामाजिक कार्यकर्ता और गौसेवा से जुड़े लोग भी शामिल रहे। इस अवसर पर संत मायाराम, संत गोविंद राम, ब्रह्मचारी कुनाल, सिद्धार्थ, मिहिर, सचिव हेमंत वच्छानी, पुरुषोत्तम दास, हेमन उस्ताद,

अमन शर्मा, बिलेश्वर डाड, रवीन्द्र कुमार जाजू, मनीषा जाजू, सिद्धि जाजू, सुभांशु जैन, शुभम सोनी, हर्षित ओझा, सृजल बिड़ला एवं अर्पित काबरा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान स्वामी हंसराम उदासीन ने कहा, गौमाता हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा की आत्मा हैं। उनकी सेवा करना ही सच्चे धर्म का पालन है। जो गौसेवा

करता है, वह वास्तव में समाज और राष्ट्र की सेवा करता है। आश्रम सद्वैद ऐसे पुण्य कार्यों में सहभागी रहेगा। इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सचिव हेमंत वच्छानी ने कहा कि भीलवाड़ा शहर में गौसेवा की इस मुहिम को जनसहयोग के बिना गति नहीं मिल सकती। सभी गौभक्त अपनी क्षमता अनुसार इस पुण्य कार्य में सहभागी बनें।

अंदाज गलत, सवाल सही!



भागवंत मान के बोलने के अंदाज की बेशक आलोचना होनी चाहिए। मगर इस कारण उनके सवालों को महत्वहीन नहीं माना जा सकता। यह प्रश्न उचित है कि मोदी की अनवरत विदेश यात्राओं से भारत को क्या हासिल होता है? पंजाब के मुख्यमंत्री भागवंत मान ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का मजाक उड़ाया, वह अनुचित है। कॉमेडियन से सियासतदां बने मान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि नरेंद्र मोदी पता नहीं किन्-किन देशों में जाते हैं, मसलन “मैनेशिया”, “गैल्वेसिया”, “टाईविसिया”। फिर वहां का सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया जाता है, जो भारतीय मीडिया में हेडलाइन्स बनता है। उन्होंने कहा कि इनमें से कई देशों की आबादी दस हजार भी नहीं है। स्पष्टतः मान ने जो नाम लिए, वैसे कोई देश दुनिया में नहीं है। चूंकि उन्होंने ये टिप्पणी प्रधानमंत्री की पांच देशों—ब्राजील, चाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया—की यात्रा के बाद की, तो लाजिमी है उसे इसी संदर्भ में देखा जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मान की टिप्पणियों को “गैर-जिम्मेदाराना और अफसोसनाक” बताया। कहा कि यह एक राज्य के उच्च पदाधिकारी को ऐसी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। बेशक, मान को उन देशों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जहां मोदी गए। किसी देश का रसूख भले उसके आकार और उसकी आर्थिक- सैनिक शक्ति से बनता हो, मगर हर मुल्क संप्रभु है। इस रूप में विश्व में उसका समान महत्व है। भले किसी देश में दस हजार लोग ही रहते हों, मगर उन व्यक्तियों की गरिमा और उनके देश का सम्मान किसी बड़ी आबादी वाले देश या वहां के बाशिंदों से कम नहीं माना जा सकता। इस लिहाज से मान के बोलने के अंदाज की बेशक आलोचना होनी चाहिए। मगर इस अंदाज के कारण मान ने जो सवाल उठाए, वे महत्वहीन नहीं माने जाएंगे। यह प्रश्न उचित है कि मोदी की अनवरत विदेश यात्राओं से भारत को क्या हासिल होता है? किस देश में कितने रायल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया, वहां का कौन-सम्मान उसे मिला, या वहां किस उद्योगपति को कौन-सा ठेका मिल गया, यह देश की विदेश नीति की कामवाबी को मानने का पैमाना नहीं हो सकता। पैमाना रणनीतिक, सामरिक एवं भू-राजनीतिक क्षेत्र में देश को होने वाले लाभ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय जो तजुबां हुआ, उससे साफ है कि ऐसे लाभ भारत को प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए भागवंत मान के सवाल निराधार नहीं हैं।

राज्यसभा में मनोनयन और चुनावी राजनीति



केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राज्यसभा की चार सीटों के लिए चार सदस्यों को मनोनीत किया है। हर बार की तरह इस बार भी नाम चौकाने वाले हैं लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव को ध्यान में रख कर नाम तय किए गए हैं। कम से कम दो नाम तो ऐसे हैं, जो विशुद्ध रूप से चुनावी राजनीति में फिट बैठते हैं। एक नाम है कि महाराष्ट्र के वकील उज्ज्वल निक्म का और दूसरा है केरल के भाजपा नेता सी सदानंदन मास्टर का। इनके अलावा दो नामों में एक इतिहासकार मीनाक्षी जैन हैं और दूसरे विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। मीनाक्षी जैन देश के जाने माने पत्रकार और संपादक गिरिलाल जैन की बेटी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुनील जैन की बहन हैं। बहरहाल, केरल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले भाजपा अपने पते बिछा रही है। राजीव चंद्रशेखर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं लेकिन तिरुवनंतपुरम सीट पर उनको हराने वाले कांग्रेस के नेता शशि थरूर को भी भाजपा साथ लाने के प्रयास में लगी है। इस बीच भाजपा के पुराने नेता सी सदानंदन मास्टर को राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया है। वे बरसों से भाजपा के साथ हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा से लड़ते रहे हैं। 1994 में सीपीएम कार्यकर्ताओं के संदिग्ध हमले में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। उनकी जिंदा शहीद कहा जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया था लेकिन वे जीत नहीं सके। अब वे राज्यसभा जाएंगे। उधर महाराष्ट्र में मुंबई सहित कई शहरों में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। इनमें मुंबई का चुनाव सबसे अहम है। इसे ध्यान में रखते हुए उज्ज्वल निक्म को राज्यसभा भेजने का फैसला हुआ है। निक्म ने मुंबई पर हुए आतंकी हमले का मुकदमा लड़ा था। जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ था। उन्होंने ही जेल में कसाब को बिरयानी खिलाए जाने का झुठा प्रचार किया था, जिससे तब की कांग्रेस सरकार कठघरे में आई थी। बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि कसाब को बिरयानी खिलाने वाली कहानी उन्होंने खूट गढ़ी थी। इस योग्यता को देखते हुए भाजपा ने उनको 2024 में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से उम्मीदवार बनाया था लेकिन वे चुनाव हार गए थे। इस तरह विधानसभा और लोकसभा हारने वाले दो लोगों को सरकार ने राज्यसभा में मनोनीत किया है।

भारत है तो मुमकिन है!

हे राम ! बिना ईंधन स्विच चालू किए ही पायलट ने विमान उड़ा दिया ! दुनिया में कभी पहले ऐसा हुआ, यह मैंने नहीं सुना ! और वह भी यात्री विमान, जिसमें 260 लोग थे! पायलट ने विमान दौड़ाने के कुछ क्षणों (सेकेंड) में ही दूसरे पायलट से पूछा— क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया है? जवाब था— नहीं तो! और उड़ान 32 सेकेंड में क़ैश ! यह सत्य कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर से उद्घाटित है ! तभी दुनिया में हैरानी है कि इस तरह एयर इंडिया का विमान क़ैश हुआ ! भला कैसे विमान उड़ाने वाले दो मानव पायलट ऐसे बेसुध हो सकते हैं जो आंखों के सामने लगा फ्यूल स्विच भी ऑन न करें और विमान को रनवे पर दौड़ा दें ! क्या दोनों पायलटों को भूलने की बीमारी थी? क्या उनके प्रशिक्षण और अनुभव में कमी थी? क्या उन्होंने शराब पी हुई थी या आलसहता मूड में थे? या यह जुगाड़ सोचा कि उड़ जाएंगे, तब ईंधन का स्विच ऑन करेंगे? अर्थात टेकऑफ लायक ईंधन तो होगा ही ! ईश्वर जाने क्या हुआ लेकिन भारत में ऐसे भी मुमकिन का सत्य दुनिया के आगे मानों बिजली कड़की ! आश्चर्य नहीं जो भारत की एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन मैदान में उतर आई है ! उसके अनुसार मानवीय भूल संभव ही नहीं है— तकनीकी खामी थी। सवाल है, टेकऑफ का बटन दबाने से पहले यह ईंधन का बटन ऑफ (या तकनीकी गड़बड़) था तो पायलट क्या विमान को खड़ा नहीं रहने देते? सो, मानवीय भूल और तकनीकी खामी को लेकर बहस भारत में तो होगी, मगर दुनिया में नहीं चलेगी। अमेरिकी अखबार “न्यूयॉर्क टाइम्स” ने एक विशेषज्ञ के हवाले से दो टुक कहा है कि रिपोर्ट में शामिल सभी बिंदु यह दर्शाते हैं कि विमान में कोई तकनीकी खामी नहीं थी, बल्कि पायलट की चूक थी। तभी सवाल है: दुनिया के विशेषज्ञ भारतीय पायलटों, जानकारों, भारतीय मीडिया की तरह क्यों नहीं मशीन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि बोंगा कंपनी को लेकर खुद अमेरिका में पक्ष-विपक्ष है? इसलिए क्योंकि दुनिया जानती है— भारत है तो सब मुमकिन है। भारत की कार्य संस्कृति में भूलने, छुपाने और दूसरों को जवाबदेह ठहराने की प्रवृति 1947 से है। फिर चाहे मामला देश को उड़ाने, देश के टेकऑफ का हो या व्यवस्था, मशीनरी के रख रखाव के तकनीकी काम हो या नागरिकों की सवारी उड़ाने के मानवीय नेतृत्व (ड्राइविंग, पायलट, अफसर-नेता) के कौशल और बुद्धि का मामला हो। तभी तो भारत के अस्सी साल दुर्घटनाओं, उन्हें छुपाने, दबाने, भूलने और दूसरों पर ठीकरा फोड़ने के हैं। जरा ताजा समय, मई-जून-जुलाई 2025 की भारत घटनाओं पर गौर करें ! शायद उम्र के उत्तरार्ध के कारण ऐसा है कि दो-तीन दिन पहले में जगुआर फाइटर जेट क़ैश में मृत स्व्वाइन लीडर लोकेन्द्र सिंह सिंधु के अंतिम संस्कार में एक महीने के बच्चे को लिए उनकी पत्नी का चेहरा देखकर द्रवित हुआ। तब मेरे दिल-दिमाग में एक तरफ भारत की सुरक्षा के अहंकारी गुमान में नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षा सलाहकार अंजित डोवाल की चेहरा था, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना की बेचारी पर सोचते हुए मन था। आपकों पता है— इस साल तीन जगुआर विमान क़ैश हुए हैं। और ये सैन्य दुर्घटनाएं नहीं हैं, बल्कि भारत की लापरवाहियों, उररदायित्वहीनता, दबाने, छुपाने, डराने और जुगाड़ की त्रासदियां हैं। चाहे जगुआर क़ैश हो या एयर इंडिया त्रासदी या नौ जून को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के करीब सुबह चलती लोकल ट्रेनों पर लटके यात्रियों के गिरने से मौत और घायल होने की विचित्र घटना (विपरीत दिशा में ट्रेनों के नजदीक से गुजरने के समय यात्रियों के बैा टकराने से) हो, सभी निष्कर्ष एक ही हैं। और वह यह कि भारत की व्यवस्था और उसके मालिकों का हर्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, मानवीय क्षमता हो या तकनीकी क्षमता— सबमें हम रामभरोसे हैं। सो, दोषी पायलट नहीं हैं, वायु सेना नहीं है, रेल प्रबंधन नहीं है, बाढ़ प्रबंधन नहीं है, बल्कि हम हिंदू हैं— हम हिंदुओं के भगवान (जैविक-अजैविक दोनों तरह के) हैं। यह मानसिकता है कि लोग मर गए तो मर गए, क्या हुआ? दुर्घटना हो गई तो हो गई, क्या हुआ? हम दोषी नहीं हैं। मशीन



दोषी है या फलां साजिश है या दुर्घटना ही नहीं है और हम तो असल में विजयी हैं ! जो हुआ वह निर्यात थी ! जो मर गए वे पुण्य, मोक्ष को प्राप्त होंगे। हां, ऐसी बेहदगी भी स्व्वाइन लीडर लोकेन्द्र सिंह सिंधु की अंत्येष्टि के दिन सुनने को मिली। उसी दिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अंजित डोवाल ने चुनौती दी कि क्या किसी के पास है कोई तस्वीर जो दिखाए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को नुकसान हुआ था ! उफ ! और यह है स्वतंत्र भारत का स्थायी सत्य-तत्त्व— कि भारत में ही मुमकिन है जो 1962 में चीन ने अक्साई चिन हड़प लिया और नेहरू और उनके रक्षा मंत्री ने कहा— “हमने हार कर गंवाया क्या? वहां तो घास भी नहीं उगती !” और इस मई-जून-जुलाई में भारत ने बार-बार मोदी, डोवाल की चुनौती सुना है कि— हमने ऑपरेशन सिंदूर में गंवाया कुछ नहीं, बल्कि इसलिए जीते क्योंकि 22 या 30 सेकेंड में हमने अचूक निशाना साधकर पाकिस्तान के भीतर मिसाइल दागी। तब भला डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल मुनीर को बुलाकर लंच क्यों कराया? चीन की लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी के शेयर क्यों उछले— जिसके जे-10सी लड़ाकू विमानों ने 22 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में भारत के लड़ाकू विमान गिराए? और सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पत्रकार के आगे यह क्यों माना कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन नुकसान हुआ था। कितना नुकसान हुआ यह अहम नहीं है, क्यों नुकसान हुआ यह बड़ा सवाल है। और उसके कारण फिर भारत ने अपनी रणनीति पर सोच-विचार किया और नौ व 10 मई की रात को बड़ी कार्रवाई की। सीडीएस की बात की पुष्टि फिर कार्रता में भारत के डिफेंस अटेंची केप्टन शिवकुमार ने भी की है। ध्यान रहे— दुनिया भर के सामरिक विशेषज्ञों, वैश्विक रिपोर्टों, विश्व राजधानियों में यह विचार नहीं है कि भारत को कितना नुकसान हुआ, बल्कि यह चिंता है कि पाकिस्तान के कंधे पर अपने लड़ाकू विमान और उनमें मिसाइलें भरकर भारत के खिलाफ जो उन्नत तकनीक, हथियारों का प्रदर्शन हुआ है वह तो अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी है। चीन निर्मित हथियारों की ऐसी धमक बनी है कि सामरिक जानकार मान रहे हैं— यह अमेरिका (जो अभी नंबर एक राष्ट्र निर्यातक है) के लिए खतरे की घंटी है। अब अमेरिका, फ्रांस, रूस से नहीं, बल्कि चीन (जो अभी चौथे नंबर पर है) से दुनिया के देश सस्ते मगर अचूक, उन्नत लड़ाकू विमान, मिसाइलें, रडार और वायु-रक्षा प्रणालियां खरीदेंगे। ध्यान रहे जिस दिन चीन निर्मित जे-10सी लड़ाकू विमानों द्वारा भारत के विमान गिराए जाने की खबर फैली, उस दिन चीन की विमान निर्माता कंपनी एवीआईसी चेंगदू एयरक्राफ्ट के शेयर तेजी से बढ़े थे। चीन निर्मित जे-10सी एक एकल-इंजन वाला बहुउद्देश्यीय जे-10 लड़ाकू विमान है और इसे बेहत

हथियार प्रणालियों और एवियोनिक्स से लैस 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है— राफेल जैसा। इसमें चीन की सबसे आधुनिक पीएल-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी थीं— जिनकी दृश्य-श्रमता से परे मारक सीमा लगभग 200–300 किलोमीटर है। पाकिस्तान को यह विमान 2022 से मिलना शुरू हो गया था। तभी ऑपरेशन सिंदूर के दिन वैश्विक मीडिया ने फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से राफेल के नष्ट होने की खबर छपी, तो दुनिया के कान खड़े हुए। वैश्विक सामरिक विशेषज्ञ जहां चीनी विमान-मिसाइल व्यवस्था की क्षमता आदि की चर्चा करते हुए थे, वहीं चीन के सोशल मीडिया पर चीनी हथियार प्रणालियों की जीत का जश्न था। और ध्यान रहे— चीन अब इससे भी उन्नत जे-10सीई, जेएफ-17 ब्लॉक III में एईएसए (Active Electronically Scanned Array) रडार जैसी तकनीकों से लैस है। वही भारत की क्या क्षमता है? यह

एक कटु तथ्य कि चार महीनों में तीन जगुआर विमान अभ्यास के दौरान क़ैश होना। संसद की स्थायी रक्षा समिति की रिपोर्ट में 2017–2022 की अवधि के दौरान भारतीय वायु सेना में कुल 34 विमान हादसों का उल्लेख है। वजह वही— जो भारत का स्थायी सत्य है: मानव त्रुटियां और तकनीकी खराबियां और दूरदृष्टि, बुद्धि-संकल्प का टोटा। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो छह स्व्वाइनों के साथ Anglo-French twin-engine Jaguar वॉरिएंट्स का अभी भी उपयोग कर रहा है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, ओमान, और नाइजीरिया जैसे देश इन्हें पहले ही रिटायर कर चुके हैं। यह विमान 1960 के दशक में विकसित हुआ और 1970 में भारत ने खरीदा। फिर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स में इसका स्वदेशी निर्माण शुरू हुआ। भारत के पास क्योंकि अपनी कोई आधुनिक घरेलू तकनीक नहीं है, इसलिए हम मजबूर हैं गुजरे जमाने के Jaguar, MiG-29, Su-30 से रक्षा का जुगाड़ बनाए हुए हैं। मोदी सरकार ने फ्रांस से कुछ राफेल जरूर खरीदे, पर न तो उसका स्वदेशी निर्माण है, और न तोजस Mk2, राफेल और अन्य मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन या नई घुबल की प्रक्रिया स्पष्ट है। यह सब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की तरह घसीट रहा है। और मान लें कि जापान हमारे लिए बुलेट ट्रेन बना दे, राफेल और उससे भी उन्नत लड़ाकू विमानों की नई खपत भी आ जाए— तो क्या गारंटी है कि फिर से ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा? वॉशिंगटन स्थित फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीजके विश्लेषक सिंगलटन ने लिखा है, राफेल आधुनिक विमान हैं, लेकिन युद्ध केवल हार्ड-प्रोफाइल खरीद का खेल नहीं है, बल्कि यह समन्वय, एकीकरण और जीवित रहने की रणनीति का मामला है। भारत की गलतियों ने ही पाकिस्तानी हथियारों को प्रभावी बनाया है। सोचिए— भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ना है (यह अनिवार्य है)। और हमारी तैयारी क्या है? इस बात को पूरी दुनिया ने जान लिया है। और जनाब अंजित डोवाल यह भी भारत का वह नुकसान है जो तस्वीर में नहीं विश्व महाशक्तियों के दिमाग में पैठा है। चीन ने तो खेर एक झटके में 22 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर से समझ लिया था। बावजूद इसके भारत के लोगों से छुपाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और चुनौती दी जा रही है कि कोई दिखाए भारत के नुकसान की फोटो ! हमने पाकिस्तान के भीतर अचूक निशाना साधा ! पर क्या कोई फोटो है पहलगाम के किसी आतंकी या एलुवामा के किसी अलका के अचूक निशाने में मारे जाने का? सबसे बड़ी बात कि ऐसा कैसा भारत ने बदला लिया पाकिस्तान में जनरल मुनीर का सशौब खल गया। वह फीड मार्शल बना, अमेरिका की सैनिक पेरंड में मेहमान और ट्रंप के साथ अकेले राजकीय भोज भी। इसलिए मेरा कहना है भारत है, ऊपर से मोदी राज है तो सब मुमकिन है।

चार पूर्व चीफ जस्टिस, सबकी एक राय!

लोकसभा, सभी विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन हो रहा है। सरकार ने 129वें संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजा गया है, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। शुरुआती प्रतिक्रिया में सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। भाजपा विरोधी लगभग सभी पार्टियों ने इसे संविधान विरुद्ध और लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ बताया। अब ऐसा लग रहा है कि संविधान की कसौटी पर इस बिल को मान्यता मिल जाएगी। इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने इस कसौटी पर बिल को सही बताया है। चारों ने संसदीय समिति के सामने कहा है कि बिल असंवैधानिक नहीं है यानी संविधान सम्मत है। एक बार यह बात स्थापित हो जाती है तो बाकी चीजों की सरकार को ज्यादा परवाह नहीं है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चार पूर्व मुख्य न्यायाधीश संसदीय समिति के सामने पेश हुए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेएस खेर, जस्टिस



यूयू ललित और जस्टिस रंजन गोगोई। इनमें से जस्टिस रंजन गोगोई को केंद्र सरकार ने रिटायर होने के बाद राज्यसभा में मनोनीत किया। लेकिन बाकी तीनों चीफ जस्टिस किसी सरकारी पद पर नहीं गए। तभी उनकी राय को अहम माना जा रहा है। रिटायर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने संसदीय समिति के सामने कहा कि यह विधेयक संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है और संविधान के

बुनियादी ढांचे यानी बैसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के भी अनुरूप है। बाकी तीनों पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का विचार बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसा लग

रहा है कि संयुक्त संसदीय समिति ने एक रणनीति के तहत चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को उनकी राय जानने के लिए आमंत्रित किया और चारों ने एक लाइन पर बिल की संवैधानिकता का समर्थन कर दिया। जाहिर है इसके बाद इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने में विपक्षी पार्टियों को मुश्किल आएगी। साथ ही कानून बनने के बाद इसे अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो वहां भी

चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की राय आड़े आएगी। चारों पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने इसकी संवैधानिक वैधता पर मुहर लगा दी है। लोकतंत्र के लिए यह अच्छा है या बुरा, इस पर न तो उनकी राय मांगी गई और न उन्होंने राय दी। वैसे भी यह राजनीतिक सवाल है, जिस पर आम जनता को फैसला देना है। हालांकि चारों पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने इसके एक प्रावधान पर सवाल उठाया है। चारों ने धारा 82 ए (5) के तहत चुनाव आयोग को दी जा रही शक्तियों पर सवाल उठाया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर चुनाव आयोग कहे कि किसी राज्य में चुनाव कराने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो वहां चुनाव नहीं होगा। इस पर पूर्व चीफ जस्टिस जेएस खेर ने यह सुझाव भी दिया कि यह फैसला सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार और संसद की भी भूमिका होनी चाहिए। इसके अलावा चारों पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने विधेयक में कुछ अस्पष्टता को शिकायत की है और कुछ सुझाव दिए हैं। लेकिन यह तय है कि उन्होंने सरकारी की मुश्किलें काफी हद तक आसान कर दी हैं।

निकोबार द्वीप का पर्यावरण न बिगाड़े!



बल्कि प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ्स) और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाएंगे। लालथिया खाड़ी, जहां ट्रांसपिरमेंट टर्मिनल प्रस्तावित है, लंदरबैक कछुओं और निकोबार मेगाफोड पक्षियों का प्रमुख प्रजनन स्थल है। 2021 में गलाथिया खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य को डिवोटिफाई कर दिया गया, जो भारत राष्ट्रीय समुद्री कछुआ संरक्षण योजना (2021) के विपरीत है। यह कछुओं और अन्य समुद्री प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि बंदरगाह निर्माण से होने वाला प्रदूषण, ड्रेजिंग, और जहाजों की आवाजही उनके प्रजनन और अस्तित्व को प्रभावित करेगी। द्वीप पर शोम्पेन और निकोबारी आदिवासी समुदाय रहते हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत

हैं। ये समुदाय अपनी आजीविका और संस्कृति के लिए जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। परियोजना से इनके पारंपरिक क्षेत्रों का 10% हिस्सा प्रभावित होगा, जिससे उनकी सामाजिक संरचना और जीविका पर खतरा मंडराएगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बाहरी लोगों के संपर्क से इन जनजातियों में रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे उनकी आबादी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकती है। ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान-सुमात्रा फॉरेस्ट लाइन पर स्थित है, जो भूकंप और सुनामी के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। 2004 की सुनामी ने इस क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन में भूकंपीय जोखिमों को कम करके आंका गया है और विशेषज्ञों का कहना है कि परि योजना के लिए साइट-विशिष्ट

भूकंपीय अध्ययन नहीं किए गए। यह एक बड़े पैमाने पर आपदा का कारण बन सकता है। परियोजना के लिए काटे गए जंगलों की भरपाई के लिए हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव है। लेकिन ये क्षेत्र निकोबार की जैव विविधता से कोई समानता नहीं रखते। यह पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में असमर्थ है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर गोपनीय रखा गया है। विशेषज्ञों का तर्क है कि केवल हवाई अड्डे का सामरिक महत्व हो सकता है, न कि पूरी परियोजना का। पारदर्शिता की यह कमी परियोजना की वैधता पर सवाल उठाती है। कांग्रेस, ने परियोजना को “पारिस्थितिक और मानवीय आपदा” करार दिया है। पर्यावरणविदों और राष्ट्रीय हरीत अधिकरण (NGT) ने 2023 में परियोजना की पर्यावरण और वन मंजूरी की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी, लेकिन इसके बावजूद परियोजना को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पारदर्शी और व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन, आदिवासी समुदायों के साथ उचित परामर्श और भूकंपीय जोखिमों का सटीक मूल्यांकन आवश्यक है। इसके साथ ही, परियोजना के आर्थिक व्यवहार्यता की पुनः समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि भारत में हाल ही में शुरू हुआ विशाखापननम का ट्रांसपिरमेंट टर्मिनल पहले से ही वैश्विक व्यापार में योगदान दे रहा है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि परियोजना क्षेत्र को CRZ 1A क्षेत्रों से बाहर रखा जाए। आदिवासी समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। भूकंपीय जोखिमों के लिए साइट-विशिष्ट अध्ययन किए जाएं। निकोबार के भीतर ही प्रतिपूरक वनीकरण पर ध्यान दिया जाए। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। इसे बचाने के लिए विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। भ्रामक तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि भारत की वैश्विक पर्यावरण संरक्षण प्रतिबद्धताओं को भी कमजोर करेंगे।

